

an>

Title: Need to waive off interest accrued on farm loans taken by farmers.

श्री राजू शेखी (हातकणंगले) : महोदय, पिछले 20 साल में देश के विभिन्न राज्यों में (विशेषकर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा) 2 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों को राहत प्रदान करने हेतु वर्ष 2008 में केन्द्र सरकार ने किसानों को ऋण माफी दे दी, लेकिन उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं और लागत मूल्य से भी कम दाम मिलने के कारण फिर से किसान बुरी तरह से ऋण के बोझ में फंस गया है। पिछले पांच वर्षों में बाढल फटना, ओलावृष्टि, पाला पड़ना, गैर-मौसमी बारिश, आंधी-तूफान, अकाल के कारण किसानों की फसल प्रतिवर्ष बर्बाद होती गई। किसानों का लागत मूल्य निरंतर बढ़ता ही गया। इसके परिणामस्वरूप किसान फिर से बुरी तरह से कर्ज में फंस गया है।

ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण किसानों को बार-बार प्राकृतिक आपदाओं से लड़ना पड़ रहा है। मजे की बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार कोई और है लेकिन सजा भुगत रहा है बेवारा बेकसूर किसान। मैं आपके माध्यम से सरकार को विनती करता हूँ कि इस देश के किसानों को फिर से स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। वैश्विक मंदी का बहाना बनाकर कारपोरेट कंपनियों ने अपने नॉन परफार्मिंग एसेट्स का आंकड़ा 1 लाख 14 हजार करोड़ रूपयों तक बढ़ा लिया और इस आर्थिक संकट से जूझ रहे बैंकों को मदद करने के लिए इस साल के बजट में वित्त मंत्री जी ने 25 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। यही न्याय देश के अन्नदाता किसानों के साथ भी होना चाहिए। देश के किसानों का आज की तिथि में जो ऋण है, उस ऋण पर तने कुल ब्याज की राशि माफ करके केवल मूलधन की राशि को अगले 10 साल में दस समान किस्तों में बिना ब्याज के वसूल किया जाए और किसानों को नये तरीके से अपनी जिन्दगी और फसल संवारने के लिए उसको नया कर्ज देने की व्यवस्था करने की तुरन्त आवश्यकता है। तभी इस देश के किसानों की आत्महत्या (सुदकुशी) की तरफ जाने वाले कदम फिर वापस खतियान की तरफ मुड़ने की उम्मीद बड़ेगी।

माननीय सभापति : श्री डी.एस.राठौड़ - उपस्थित नहीं।